

जागत



पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

गांव

चौपाल से
भोपाल तक

भोपाल, सोमवार, 10-16 फरवरी 2025 वर्ष-10, अंक-43

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरेना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ:-8, मूल्य:- 2 रुपए

दमोह के सीतानगर में 515 एकड़ में बनेगा गौ-अभयारण्य, सड़क पर घूम रहे बेसहारा मवेशियों को मिलेगा आसरा

मप्र के 15 जिलों में गौ वन्य बिहार बनाएगी सरकार

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा दमोह जिले सहित 15 अन्य जिलों में गो वन्य बिहार स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है, जहां बेसहारा गौवंश को सुरक्षित रूप से रखा जाएगा। पशुपालन मंत्री लखन पटेल ने दमोह में मीडिया से चर्चा के दौरान इस योजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री इस समस्या को गंभीरता से ले रहे हैं, क्योंकि सड़कों पर आवारा गौवंश के कारण सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि छोटी-छोटी गौशालाओं के बजाय बड़े गौ वन्य बिहार बनाए जाएंगे, जो अत्याधुनिक

सुविधाओं से लैस होंगे। इन अभयारण्यों में हजारों मवेशियों के लिए चारा, चिकित्सा, आश्रय और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके लिए सरकार ने 15 जिलों में सैकड़ों एकड़ भूमि आवंटित करने की योजना बनाई है। पथरिया विधानसभा क्षेत्र के सीतानगर में 515 एकड़ भूमि में एक हाईटेक गौ अभयारण्य स्थापित किया जाएगा। इस अभयारण्य में लगभग दस हजार बेसहारा गौवंश को आश्रय दिया जाएगा। यहां आधुनिक गौशाला, प्रशिक्षण केंद्र, वेटनरी अस्पताल, गेस्ट हाउस, बड़े शेड और जैविक खाद निर्माण की भी व्यवस्था होगी।



हादसों में हो रहा इजाफा

सड़क पर बेसहारा गौवंश की बढ़ती संख्या के कारण सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही है, जिससे वाहन चालकों और मवेशियों की मौतें हो रही हैं। विशेष रूप से दमोह-जबलपुर मार्ग के सिग्रामपुर क्षेत्र में बड़ी संख्या में गौ वंश सड़कों पर बेठे दिखाई देते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने गौ वन्य बिहार परियोजना को

प्राथमिकता दी है।

सरकार का अहम कदम

पशुपालन मंत्री पटेल ने बताया कि इन 15 गो वन्य बिहारों की स्थापना जल्द ही शुरू होगी, जिससे आवारा गौवंश की समस्या का स्थायी समाधान हो सकेगा। सरकार का यह प्रयास गौ वंश संरक्षण और सड़कों पर हो रही दुर्घटनाओं को रोकने की दिशा में एक अहम कदम साबित होगा।

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड विकास के लिए प्रयासरत

भोपाल। किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री एदल सिंह कपाना ने कहा है कि मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड प्रदेश के विकास के लिए प्रयासरत है। किसान सड़क निधि अंतर्गत अब तक 7616.41 करोड़ रुपये अर्जित किए गए हैं। इस निधि से प्रदेश की सड़कों के विकास के लिए 4107.81 करोड़ रुपए मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित किए गए। किसान सड़क निधि से 2020.26 करोड़ अन्य विभागों के कार्यालयों को जारी किए गए हैं। मंत्री ने कहा कि कृषि अनुसंधान एवं अधीकरण विकास निधि अंतर्गत अब तक 756.95 करोड़ अर्जित किए गए हैं। इस राशि से 753.40 करोड़ विभिन्न संस्थाओं को अनुदान स्वरूप प्रदान किए गए हैं। गौ-संरक्षण तथा संवर्धन निधि में 479.30 करोड़ प्राप्त हुए हैं, जिसमें से मध्यप्रदेश गौ-पालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड को 478.50 करोड़ समस्त जिलों की गौ-शालाओं को अनुदान स्वरूप प्रदान किए गए हैं।

संसद में बोले-पीएम मोदी-300 रुपए से कम में सरकार दे रही यूरिया

आज दुनियाभर के बाजारों में मोटा अनाज यानी श्रीअन्न शान बढ़ाएगा

भोपाल। जागत गांव हमार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपना भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने खेती-बाड़ी के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि 2014 से अभी तक खेती के बजट में 10 गुना वृद्धि की गई है। पहले यूरिया मांगने पर लाठी पड़ती थी। रात भर कतारों में खड़ा होना पड़ता था। खाद किसानों के नाम पर निकलती थी लेकिन खेत तक नहीं पहुंचती थी। कहीं और पहुंच जाती थी। आज किसान को पर्याप्त खाद मिल रही है। कोविड के दौरान जब पूरी दुनिया में इसकी कमी थी, तब भारत में ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा, हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र को छूने का प्रयास किया है। किसान एक मजबूत स्तंभ हैं। कोविड संकट के बाद दुनिया में दाम अनाज-शनाप बढ़ गए। यूरिया का जो बारा 3000 का पड़ रहा है, सरकार ने झेला और किसान को 300 रुपए में दिया। किसान को ज्यादा लाभ मिले, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। किसान को सस्ती खाद मिले, इसके लिए 12 लाख करोड़ खर्च किया गया है। प्रधानमंत्री ने संसद में कहा, हमने रिकॉर्ड एमएसपी भी बढ़ाया और

किसान को सस्ती खाद मिले, इसके लिए 12 लाख करोड़ खर्च किए गए



सिंचाई परियोजनाओं पर बड़ा काम

प्रधानमंत्री ने कहा कि सिंचाई पर बड़ा काम हो रहा है। 100 से अधिक सिंचाई परियोजनाओं को दृष्टकों से लटकी हुई थी, हमने उस पर अभियान चलाया ताकि किसानों के खेत में पानी पहुंचे। नदियों को जोड़ने का विजन बाबा साहब अंबेडकर का था। इसकी पकलत बाबा साहब ने की थी, लेकिन सालों तक, दृष्टकों तक कुछ नहीं हुआ। आज हमने केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट और पार्वती-कालीसिंध प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि हर देशवासी का सपना होना चाहिए कि दुनिया के इंडिया टैबल पर गेड इन इंडिया फूड प्लेटेक्ट क्यों नहीं हो। आज खुशी की बात है कि भारत की चाय और हमारी कॉफी भी दुनिया में अपनी महक फैला रही है।

कॉफी भी दुनिया में धूम मचाएगी

अपनी हल्दी की कोविड के बाद दुनिया में सबसे अधिक मांग बढ़ी है। हमारी कॉफी भी दुनिया में धूम मचावी चाहिए। बिहार का मखाना दुनिया में पहुंचने वाला है। दुनिया के बाजारों में मोटा अनाज यानी श्रीअन्न शान बढ़ाएगा। अपने संबोधन की शुरुआत में पीएम मोदी ने इथेनॉल ब्लेंडिंग की तारीफ में कहा कि इससे सरकार के 1 लाख करोड़ बचे हैं जिसका फायदा किसानों को मिल रहा है। इसी के साथ उन्होंने पीएम सुरेश्वर स्कीम, सॉल्व हेथ कार्ड, फिशरीज और ड्रेन दीदी स्कीम की भी सराहना की।

बीते दशक में तीन गुना अधिक हमने खरीदी की है। किसान को लोन मिले, आसान लोन मिले, सस्ता लोन मिले, इसके लिए उसमें भी तीन गुना वृद्धि की गई है। पहले प्राकृतिक आपदा में किसान को उसके हाल पर छोड़ दिया जाता था। हमारे सेवाकाल में पीएम फसल बीमा के तहत 2 लाख करोड़ किसानों को मिले हैं। सिंचाई के लिए हमने कदम उठाए हैं। संविधान की बात करने वालों को ज्यादा ज्ञान नहीं है। पानी को हिकर बाबा साहब का विजन इतना क्लियर था कि आज भी हम लोगों को प्रेरणा देता है। हमने सौ से अधिक दृष्टकों से लटकी सिंचाई परियोजनाएं पूरा करने का अभियान चलाया।

गेहूं की बोवनी का बना रिकॉर्ड, कम होगी बढ़ते दाम की टेंशन

भोपाल। जागत गांव हमार

रबी सीजन की मुख्य फसल गेहूं की बुवाई ने इस साल रिकॉर्ड बना दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के मुताबिक जनवरी तक देश में 324.88 लाख हेक्टेयर में गेहूं बोया जा चुका है, जो 2023-24 की इसी अवधि के मुकाबले 6.55 लाख हेक्टेयर अधिक है। गेहूं की बंपर बोवनी हुई है। इससे उत्पादन बढ़ेगा और फिर इसके दाम को लेकर जो टेंशन बनी हुई है वह कम हो सकती है। देश में गेहूं का सामान्य रकबा

312.35 लाख हेक्टेयर ही है। इस हिसाब से गेहूं का वर्तमान रकबा बहुत अच्छा माना जा रहा है। हालांकि, अभी बोवनी का फाइनल आंकड़ा नहीं आया है। पिछले तीन साल से देश में गेहूं का दाम उसकी एमएसपी से अधिक है। इसीलिए किसानों ने इसकी अच्छी बोवनी की है। केंद्र सरकार ने साल



2025-26 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपए किंवटल तय किया है, जबकि किंवटल औसत लागत 1182 रुपए आती है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक 2023-24 के दौरान गेहूं की बोवनी का फाइनल आंकड़ा

में 1132.92 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन हुआ था। उम्मीद है कि 2025 में जब गेहूं की बोवनी का फाइनल आंकड़ा आया तब पिछले साल का रिकॉर्ड टूटेगा। बहरहाल, इस समय देश में गेहूं का औसत दाम 2955 रुपए किंवटल चल रहा है, जो 2024-25 के लिए तय एमएसपी के मुकाबले 680 रुपए किंवटल ज्यादा है। ये तो रही सिर्फ गेहूं की बात। रबी फसलों का फाइनल आंकड़ा 31 जनवरी तक 661.03 लाख हेक्टेयर हो गया है।

खेती-किसानी के विकास के लिए किया जा रहा काम

देश में प्याज, आलू-टमाटर का होगा बंपर उत्पादन

भोपाल | जागत गांव हमार

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने अलग-अलग बागवानी फसलों के क्षेत्र और उत्पादन के 2023-24 के अंतिम अनुमान और 2024-25 के प्रथम अग्रिम अनुमान जारी कर दिए हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बागवानी फसलों के इन आंकड़ों को मंजूरी देने के साथ ही इन्हें जारी करते हुए बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार द्वारा खेती-किसानी के विकास के लिए निरंतर काम किया जा रहा है और कृषि मंत्रालय द्वारा अनेक योजनाओं के माध्यम से किसानों को निरंतर बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके फलस्वरूप बागवानी उत्पादन भी रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ रहा है। वर्ष 2023-24 में देश में बागवानी उत्पादन 354.74 मिलियन टन और बागवानी क्षेत्र 29.09 मिलियन हेक्टेयर होने का अनुमान है। वर्ष 2022-23 की तुलना में 2023-24 में 2.28 परसेंट (0.65 मिलियन हेक्टेयर) क्षेत्र में वृद्धि देखी गई है। इसी प्रकार, देश में वर्ष 2024-25 (प्रथम अग्रिम अनुमान) में बागवानी उत्पादन लगभग 362.09 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो कि वर्ष 2023-24 (अंतिम अनुमान) की तुलना में लगभग 73.42 लाख टन (2.07 प्रतिशत) अधिक है।



अंतिम अनुमान...2023-24 के मुख्य बिंदु

- वर्ष 2023-24 में देश में बागवानी उत्पादन 354.74 मिलियन टन और बागवानी क्षेत्र 29.09 मिलियन हेक्टेयर होने का अनुमान है। वर्ष 2022-23 की तुलना में 2023-24 में 2.28 परसेंट या 0.65 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में वृद्धि देखी गई है।
- वर्ष 2023-24 में फलों, सुगंधित और औषधीय पौधों, शहद, फूलों, बागान फसलों और मसालों के उत्पादन में वर्ष 2022-23 से वृद्धि देखी गई है।
- वर्ष 2023-24 में फलों का उत्पादन 1129.78 लाख टन रहने का अनुमान है, जिसका मुख्य कारण आम, केला, शरीफा, अंगूर और कटहल के उत्पादन में वृद्धि होना है।
- सब्जियों का उत्पादन 2072.08 लाख टन होने का अनुमान है। टमाटर, लौकी, गोभी, गाजर, टैपिओका, करेला और खीरे के उत्पादन में वृद्धि देखी गई है।
- 2023-24 में प्याज का उत्पादन 242.67 लाख टन होने का अनुमान है, जबकि पिछले वर्ष यह 302.08 लाख टन था।
- टमाटर का उत्पादन 2022-23 की तुलना में 2023-24 में 4.40 परसेंट बढ़कर 213.23 लाख टन होने का अनुमान है।
- सुगंधित और औषधीय पौधों के उत्पादन में 19.44 परसेंट अर्थात् 2022-23 में 6.08 लाख टन से बढ़कर 2023-24 में 7.26 लाख टन तक की वृद्धि देखी गई।
- देश में फूलों का उत्पादन 2022-23 में 30.97 लाख टन से बढ़कर 2023-24 में 35.35 लाख टन होने का अनुमान है।
- वर्ष 2023-24 में बागान फसलों का उत्पादन 176.66 लाख टन होने का अनुमान है, जो कि वर्ष 2022-23 में 170.49 लाख टन से अधिक है।
- 2023-24 में मसालों का कुल उत्पादन 124.84 लाख टन होने का अनुमान है। जीरा, सौंफ, अदरक और लाल मिर्च के उत्पादन में वृद्धि देखी गई।

2024-25 (प्रथम अग्रिम अनुमान) के मुख्य बिंदु

- देश में वर्ष 2024-25 (प्रथम अग्रिम अनुमान) में बागवानी उत्पादन 362.09 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो कि वर्ष 2023-24 (अंतिम अनुमान) की तुलना में 73.42 लाख टन (2.07 फीसदी) अधिक है।
- फलों, सब्जियों, फूलों और बागान फसलों के उत्पादन में वृद्धि की परिकल्पना की गई है। 2024-25 में फलों का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 2.48 लाख टन बढ़कर 1132.26 लाख टन तक पहुंचने की उम्मीद है, जिसका मुख्य कारण आम, अंगूर और केले के उत्पादन में वृद्धि होना है।
- सब्जियों का उत्पादन वर्ष 2023-24 के 2072.08 लाख टन से बढ़कर 2024-25 में 2145.63 लाख टन होने की उम्मीद है। प्याज, आलू, टमाटर, हरी मिर्च, फूलगोभी और मटर में वृद्धि की उम्मीद है।
- वर्ष 2024-25 में प्याज का उत्पादन पिछले वर्ष लगभग 242.67 लाख टन की तुलना में लगभग 288.77 लाख टन होने की उम्मीद है, जो कि 46.10 लाख टन अधिक है।
- आलू उत्पादन 595.72 लाख टन तक पहुंचने की उम्मीद है, जो पिछले साल की तुलना में 25.19 लाख टन अधिक है।
- टमाटर का उत्पादन पिछले वर्ष के लगभग 213.23 लाख टन की तुलना में लगभग 215.49 लाख टन होने की उम्मीद है, जो 1.06 परसेंट अधिक है।
- बागान फसलों का उत्पादन 179.37 लाख टन होने का अनुमान है, जो 2023-24 में 176.66 लाख टन (1.53 फीसदी) से अधिक है। मसालों का उत्पादन 119.96 लाख टन होने का अनुमान है। लहसुन और हल्दी के उत्पादन में वृद्धि देखी गई है।

2024-25 में 8.14 लाख मीट्रिक टन आयात किया

दुनिया में अरहर दाल का सबसे बड़ा उत्पादक भारत, दाम में 36 प्रतिशत तक आया उछाल

भोपाल | जागत गांव हमार

दुनिया भर में दलहन फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक होने के बावजूद भारत बड़े पैमाने पर इसका आयात करने पर मजबूर है। क्योंकि बढ़ती जनसंख्या के हिसाब से उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। तुअर यानी अरहर बेहद लोकप्रिय दाल है। मांग और आपूर्ति में भारी अंतर की वजह से पिछले दो साल में ही इसके दाम में लगभग 36 फीसदी का उछाल आ चुका है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के मुताबिक 1 से 29 जनवरी 2023 के बीच देश में अरहर दाल का थोक दाम 9953.97 रुपए प्रति किंटल था, जो इसी अवधि के दौरान 2025 में बढ़कर 13,527.8 रुपए प्रति किंटल तक पहुंच गया, जबकि, इसका एमएसपी मात्र 7550 रुपए किंटल है। शाकाहारी लोगों के लिए दालें प्रोटीन का प्रमुख स्रोत हैं। तमाम भारतीयों के खाने में दालें किसी न किसी रूप में होती हैं। ऐसे में हम जहाँ दालों के सबसे बड़े उत्पादक हैं।

वहीं सबसे बड़े उपभोक्ता भी हैं। बहरहाल, तुअर दाल की बात करते हैं, जिसकी मांग और घरेलू उत्पादन में लगभग 10 लाख मीट्रिक टन का अंतर है। सालाना लगभग 45 लाख टन की जरूरत है, जबकि उत्पादन 35 लाख टन ही रह गया है। ऐसे में हमें लोगों की दालों की मांग पूरा



करने के लिए आयात का सहारा लेना पड़ रहा है, जिसकी वजह से इसके दाम में तेजी का रुख कायम है।

कम हो गया उत्पादन

भारत ने 2020-21 में 43.16 लाख मीट्रिक टन तुअर दाल का उत्पादन किया था, लेकिन उसके बाद मौसम के बदलाव और फसल में बीमारियों के लगने की वजह से इसमें कमी आने लगी। साल 2022-23 में उत्पादन सिर्फ 33.12 लाख मीट्रिक टन रह गया। हालांकि उसके बाद इसमें वृद्धि का रुख शुरू हुआ है और 2024-25 में यह बढ़कर 35.02 लाख मीट्रिक टन हो गया है। इसके बावजूद हम अपनी मांग जिन्ना उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें दूसरे देशों से आयात पर निर्भर रहना पड़ रहा है। नतीजतन अरहर दाल का दाम कम होने का नाम नहीं ले रहा है।

कितना है रिटेल प्राइस

इस समय देश में तुअर दाल का दाम 200 रुपए किलो तक है। ब्रांड के हिसाब से दाम में अंतर है। उपभोक्ता मामले विभाग के प्राइस मॉनिटरिंग डिवीजन के अनुसार देश में अरहर दाल का अधिकतम रिटेल प्राइस 187 रुपए किलो रहा, जबकि जनवरी 2023 को देश में तुअर दाल का अधिकतम दाम 132 रुपए किलो था।

सबसे बड़ा उत्पादक और आयातक

फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, 2022-23 में, वैश्विक स्तर पर 53.3 लाख मीट्रिक टन अरहर दाल (तुअर) का उत्पादन हुआ था। कुल उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 79 फीसदी की रही। भारत के अलावा मलावी, म्यांमार, तंजानिया और केन्या प्रमुख तुअर उत्पादक देश हैं। भारत में महाराष्ट्र और कर्नाटक तुअर के सबसे बड़े उत्पादक सूबे हैं। भारत ने वर्ष 2024-25 के दौरान 8.14 लाख मीट्रिक टन तुअर का आयात किया, जो पिछले साल की तुलना में 85.02 फीसदी अधिक है। पिछले साल यानी 2023-24 में तुअर आयात 4.40 लाख मीट्रिक टन ही था। साल 2024-25 का आयात अप्रैल 2024 से अक्टूबर 2024 तक का है।

मध्यप्रदेश में किसानों के लिए किए जा रहे नवाचार

भोपाल। राज्य सरकार

किसानों के कल्याण के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में किसानों के हित में कई नवाचार किए जा रहे हैं और उपलब्धियां हासिल हो रही हैं। 2024-25 में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा मिशन अंतर्गत 2 लाख से अधिक किसानों को लाभांशित किया गया है। मध्यप्रदेश राज्य मिलेट मिशन अंतर्गत कृषकों को डेढ़ करोड़ रुपए से अधिक राशि का लाभ प्रदान किया गया है। वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनांतर्गत 207 करोड़ के प्रोजेक्ट एवं 644 करोड़ की वार्षिक कार्ययोजना स्वीकृत की गई है। रबी विपणन वर्ष 2023-24 में कुल 81 लाख कृषक आवेदनों का 41.49 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के लिए बोर्माकन किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत 25.79 लाख कृषकों को 755 करोड़ राशि के दावा भुगतान किए गए। किसानों को शीघ्रता से हरसंभव दावा भुगतान करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

बीज में उपलब्धि खरीफ 2024 में 22.87 लाख किंटल प्रमाणित बीज का शासकीय, सहकारी एवं पंजीकृत निजी बीज उत्पादक संस्थानों के माध्यम से वितरण किया गया। प्रदेश के कृषकों को उच्च गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्धता के लिए संभोग स्तर पर 10 बीज परीक्षण प्रयोगशालाएं संचालित हैं।

सख्ती भी बरती वर्ष 2023-24 में 21920 बीज नमूना विश्लेषण के लक्ष्य के विरुद्ध 17376 बीज नमूने लिए जाकर 14085 नमूने बीज परीक्षण प्रयोगशाला में विश्लेषित किए गए। जिसमें 12955 मानक व 1130 अमानक गए। अमानक नमूनों में 1070 विकर्य प्रतिबन्धित, 186 लाइसेंस विल्टन और 70 लाइसेंस विरुद्ध किए गए।

गाज भी मिले खरीफ 13140 बीज नमूना विश्लेषण के लक्ष्य के विरुद्ध 10235 नमूने लिए गए। 10212 विश्लेषित किए गए। जिसमें 9422 मानक, 790 अमानक मिले। अमानक नमूनों में 534 विकर्य प्रतिबन्धित, 25 लाइसेंस विल्टन तथा 8 लाइसेंस विरुद्ध किए गए।

रेनफेड ऐरिया डेवलपमेंट वर्ष 2024-25 में स्वीकृत कार्य योजना अनुसार 3629.05 लाख रुपये का अर्बुद जिलों को जारी किया गया, जिसके विरुद्ध जिलों द्वारा 1991.45 लाख का व्यय किया गया है। योजनांतर्गत वर्ष 2023-24 में 144.35 लाख व्यय किए जाकर 1392 हेक्टेयर क्षेत्र के कृषकों को लाभान्वित किया गया। सब मिशन ऑन एगोकरेस्ट्री योजना में वर्ष 2023-24 में 141 लाख व्यय कर चार नर्सरियों को लाभान्वित किया गया।

बलराम तालाब पीएम कृषि सिंचाई योजना बलराम तालाब में कृषकों को स्वयं के व्यय पर तालाब निर्माण निर्माण पर कृषकों को लागत राशि का 40 प्रतिशत राशि 80 हजार, लघु सौरान्वत कृषकों को लागत राशि का 50 प्रतिशत राशि, 80 हजार तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों को लागत राशि का 75 प्रतिशत अधिकतम एक लाख का अर्बुद दिए जाने का प्रावधान निश्चित है।

भारत नारियल उत्पादन में दुनिया में नंबर एक है। आंध्रप्रदेश में नारियल के उत्पादन को बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं। इसलिए आंध्रप्रदेश में उत्पादन बढ़ाने और क्षेत्र के विस्तार के लिए अनेक प्रयास शुरू किए गए हैं। नारियल में आने वाली अलग-अलग प्रकार की बीमारियों से निपटने के लिए आईसीएआर ने अनेक उपाय किए हैं। नई फसलें विकसित करने के साथ ही सहायता राशि भी उपलब्ध कराई गई है। पीएम फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। यह बातें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संसद में कृषि से जुड़े सवालों के जवाब में कहीं।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले-फसल बीमा योजना किसानों के लिए बनी वरदान

-किसानों को ट्रेनिंग देने के लिए कृषि सखी और कम्प्यूनिटी परसन नियुक्त होंगे
-इनपुट उपलब्ध कराने 10 हजार बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर भी शुरू किए जाएंगे

35 हजार करोड़ प्रीमियम पर किसानों को मिले 1.72 लाख करोड़ रुपए

भोपाल। जागत गांव हमार

शिवराज ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संसद में प्रश्नकाल के दौरान कृषि से जुड़े सवालों के जवाब देते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाना केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। केंद्र सरकार कृषि एवं किसान कल्याण के लिए संकल्पित है और लगातार इस क्षेत्र में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आज नारियल उत्पादन में हमारा देश नंबर एक पर पहुंचा है, जिसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी की उत्पादन बढ़ाने की नीति है। वर्ष 2014-15 के दौरान नारियल उत्पादन 140 लाख मीट्रिक टन था, जो अब बढ़कर 153.29 लाख मीट्रिक टन हो गया है। विश्व में हमारी उत्पादकता सबसे अधिक है। आंध्रप्रदेश में भी उत्पादकता 11 मीट्रिक टन है।

रोगों से बचाएगा आईसीएआर

कृषि मंत्री ने कहा कि आंध्रप्रदेश में नारियल उत्पादन बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं, इसलिए आंध्रप्रदेश में उत्पादन बढ़ाने और क्षेत्र विस्तार के लिए अनेकों प्रयास प्रारंभ किए गए हैं। पिछले 10 वर्षों में आंध्रप्रदेश में कुल नारियल क्षेत्र का विस्तार 12,391 हेक्टेयर किया गया है, जिससे 12,406 किसान लाभान्वित हुए हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने भी लगातार प्रयत्न किए हैं कि जो अलग-अलग प्रकार की बीमारी नारियल के पामट्री के पर आती है, उस पर शोध किया जाए और शोध करने के बाद उनसे निपटने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। कर्नाटक व केरल में कीटों और बीमारियों की समस्या के लिए किसानों को 50.56 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई है। केरल हो, कर्नाटक या तमिलनाडु, जब ऐसी बीमारियां आती हैं तो हम लगातार प्रयत्न करते हैं कि बीमारियों का नियंत्रण भी किया जाए और किसानों को सहायता भी दी जाए।



कृषि मंत्री ने कहा कि आंध्रप्रदेश में नारियल उत्पादन बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं, इसलिए आंध्रप्रदेश में उत्पादन बढ़ाने और क्षेत्र विस्तार के लिए अनेकों प्रयास प्रारंभ किए गए हैं। पिछले 10 वर्षों में आंध्रप्रदेश में कुल नारियल क्षेत्र का विस्तार 12,391 हेक्टेयर किया गया है, जिससे 12,406 किसान लाभान्वित हुए हैं।

23 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों ने फसल बीमा का चयन

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देश के किसानों के लिए वरदान बनकर आई है, आज यह बीमा आवेदनों के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है। कृषि राज्य का विषय है और ये योजना स्वैच्छिक है, इसलिए योजना को चुनना राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। 23 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों ने इस योजना का चयन किया है, लेकिन कुछ राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अपने यहां की योजना भी चलाते हैं। उन्होंने कहा कि किसानों का नुकसान हो तो उसकी भरपाई हो जाए, यह मोदी सरकार की नीति है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी बागवानी फसलों के लिए मौसम आधारित फसल बीमा योजना राज्य सरकार के प्रस्तावों पर केंद्र सरकार लागू करती है। गैर श्रेणी किसानों के भी 5 करोड़ से ज्यादा आवेदन आए हैं, जिनमें 35,000 करोड़ रुपए के किसान प्रीमियम पर 1.72 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे गए हैं।

केला नुकसान पर किसानों को प्रति हेक्टेयर 2 लाख रुपए का भुगतान

आंध्रप्रदेश में केले का बहुत अच्छा उत्पादन होता है और अलग-अलग राज्य सरकारें अपने किसानों के हित के लिए कवरम उठाती हैं। आंध्रप्रदेश में केले के नुकसान पर 2 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से राहत की राशि दी जाती है। पहले जो फसल बीमा योजना थी, वह बहुत डिफिकल्ट थी। कई बार 6 से 8 महीने 1 साल तक ला जाता था, लेकिन अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत यह तय किया गया है कि फसल कटाई के अतिरिक्त एक महीने के बाद राज्य सरकार रिपोर्ट भेजे और वह रिपोर्ट मिलने के बाद फसल नुकसान का जो दावा है, उसका शुभान्त किसानों को कर दिया जाए। हमने ये भी तय किया है कि अगर राज्य सरकार उपाज के अंकड़े भेज दें और उसमें बीमा कंपनी देशी करेगी तो 12 फीसदी उन्हें ब्याज देना पड़ेगा।

27 राज्यों की 1410 मंडिया ई-नाम पोर्टल से जुड़ीं

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमने छोटे किसानों को कवर करने का पूरा प्रयास किया है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को ई-नाम के संयोजन और स्थानीय जरूरत को पूरा करने के लिए फंड दिया जा रहा है। किसानों को अपने उपज कहीं और व ले जाना पड़े, वो मंडी में ही ई-नेम प्लेटफॉर्म के साथ व्यापार कर सकें इसके लिए बिहार की 20 बाजार स्थितियों को ई-नाम प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ा गया है। भारत सरकार ने ई-नेम प्लेटफॉर्म में मंडियों को जोड़ने का लक्ष्य 2023 में 23 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 1410 मंडियों को ई-नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है।

नेचुरल फार्मिंग से मिट्टी की सेहत सुधरी

केंद्र सरकार नेचुरल फार्मिंग पर खास ध्यान दे रही है और इसके लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन का संचालन किया जा रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को नेचुरल फार्मिंग के लिए प्रेरित किया जाएगा। राज्यों को नेचुरल फार्मिंग के लिए क्लस्टर आवंटन किए गए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को ट्रेनिंग देने के लिए हर क्लस्टर में 2 कृषि सखी और कम्प्यूनिटी रिसोर्स परसन की नियुक्ति की जाएगी। यह लोग किसानों को नेचुरल तरीके से खेती करने के लिए प्रेरित करेंगे और टिकाऊ विधियों का तरीका बताने के साथ ही खेती के फायदे बताएंगे और उनका मार्गदर्शन करेंगे। इनपुट उपलब्ध कराने के लिए 10 हजार बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर भी शुरू किए जाएंगे।

कृषि का 19 हजार करोड़ बजट बढ़ा

केंद्र सरकार खेती के विकास पर तेज गति से काम कर रही है। यही वजह है कि 1 फरवरी को आए केंद्रीय बजट में कृषि से जुड़े क्षेत्रों के लिए 19 हजार करोड़ बजट बढ़ाकर 1.71 लाख करोड़ रुपए आवंटन का प्रस्ताव रखा गया है। राष्ट्रीय खेती विकास योजना के तहत दिए जाने वाले बजट में भी बढ़ोत्तरी की गई है। 2025-26 के लिए 8500 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है, जबकि इससे पहले बीते वित्तवर्ष में 6000 करोड़ रुपये ही बजट रखा गया था। इस हिसाब से कृषि विकास योजना के लिए 2500 करोड़ बजट में बढ़ोत्तरी की गई है।

केमिकल से उर्वरा शक्ति घट रही

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने संसद में कृषि से जुड़े सवालों के जवाब में कहा कि केमिकल फर्टिलाइजर के अनियंत्रित और अधिक इस्तेमाल की वजह से आज धरती की उर्वरक क्षमता कम हो रही है। जैविक कार्बन घट रहा है, मित्र कीट मारे जा रहे हैं, जल धारण की क्षमता घटती जा रही है। उन्होंने कहा कि नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग को 15 नवंबर 2024 को मंजूरी दी गई है। प्राकृतिक खेती के लिए इस मिशन के माध्यम से हम किसानों को प्रेरित करने का प्रयास कर रहे हैं।

2 लाख किसान प्राकृतिक खेती करेंगे

कृषि मंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार प्राकृतिक खेती पर पहले से ही काम कर रही है। कुछ अन्य राज्य सरकारें भी प्राकृतिक खेती पर काम कर रही हैं। अभी प्राकृतिक खेती मिशन के तहत महाराष्ट्र को 1709 क्लस्टर का आवंटन किया गया है। 85,450 हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती की जाएगी, जिसमें 2.13 लाख किसान प्राकृतिक खेती की शुरुआत करेंगे।

मिट्टी का स्वास्थ्य सुधारा

कृषि मंत्री ने कहा कि किसान धीरे-धीरे प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ें, पूरी जमीन पर नहीं, लेकिन जमीन के एक हिस्से में प्राकृतिक खेती प्रारंभ करें और उसके परिणामों के आधार पर बाकी किसान भी सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसके लिए प्राकृतिक खेती का एक मिशन बनाया गया है। उन्होंने कहा कि रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से मिट्टी पर बहुत बुरा असर पड़ता है, लेकिन प्राकृतिक खेती मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार लाती है और इसलिए यह आशंका कि इससे उत्पादन बहुत घट जाएगा, यह पूरी तरह से सही नहीं है। प्राकृतिक खेती ठीक विधि से किसान कर सकें।

कृषि सखी नियुक्त की जाएंगी

सही विधि से प्राकृतिक खेती करने के लिए किसानों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए हम प्रत्येक क्लस्टर में दो कृषि सखी और कम्प्यूनिटी रिसोर्सपरसन नियुक्त करेंगे। प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे। जो इनपुट लगते हैं, उनको आसानी से उपलब्ध कराने के लिए 10 हजार बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर भी प्रारंभ करेंगे। उनके लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करेंगे। किसानों को अपने खेत पर भी इनपुट बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा, अगर ठीक इनपुट डाले जाएंगे तो उत्पादन नहीं घटेगा।

मिट्टी-जल संरक्षण के लिए वाटरशेड यात्रा



कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जल है तो कल है और मिट्टी है तो जीवन है, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जल लाए धन-धान्य इस थीम के आधार पर 5 फरवरी से वाटरशेड यात्रा का प्रारंभ कर रहे हैं। मिट्टी के क्षरण को रोकने और जल संरक्षण के लिए जागरूकता के उद्देश्य से यह यात्रा 26 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 6673 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत 13587 गांवों को कवर करेंगी।

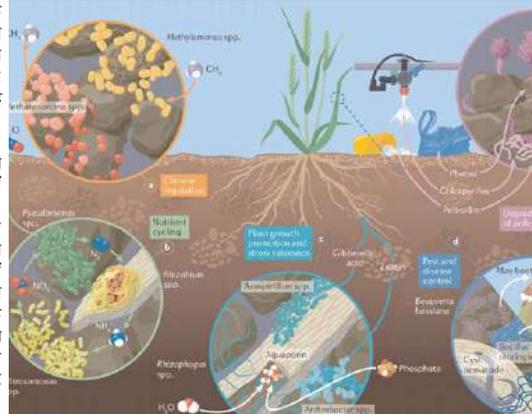
मृदा माइक्रोबायोटम: कृषि उत्पादकता को आकार देने वाली एक अदृश्य दुनिया

मृदा माइक्रोबायोटम, मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्मजीवों का समूह है। इनमें बैक्टीरिया, आर्किया, कवक, वायरस, और सूक्ष्मजीव शामिल हैं। ये सूक्ष्मजीव मिट्टी की संरचना, पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण, और रोगाणुओं को दबाने में मदद करते हैं। मृदा माइक्रोबायोटम, कृषि, खाद्य उत्पादन, और जलवायु विनियमन में अहम भूमिका निभाता है। बढ़ती जनसंख्या के संदर्भ में वैश्विक खाद्य उत्पादन के लिए मृदा स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। माइक्रोबायोटम, सूक्ष्मजीवों और उनकी गतिविधियों का एक संयोजन, संदूषकों को बायोडिग्रेडिंग, मिट्टी की संरचना को बनाए रखने, पोषक तत्वों के चक्र को नियंत्रित करने और जैविक और अजैविक तनावों के प्रति पौधों की प्रतिक्रियाओं को

मिट्टी, जिसे अक्सर हल्के में लिया जाता है, एक जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें पृथ्वी पर किसी भी अन्य आवास की तुलना में अधिक जैव विविधता है। दृश्यमान केंचुओं और कोंड़ों से परे अद्वितीय जटिलता की एक सूक्ष्म दुनिया है। यह मिट्टी माइक्रोबायोटम, बैक्टीरिया, कवक, आर्किया, वायरस और प्रोटिस्ट का एक समुदाय, केवल छोटे जीवों का एक संग्रह नहीं है; यह पौधों के स्वास्थ्य और कृषि को सफलता के लिए गहन निहितार्थों वाला एक गतिशील, परस्पर जुड़ा हुआ नेटवर्क है। **छिपी हुई दुनिया का परिचय:** दशकों से, कृषि ने पौधों के उत्पादन के ऊपरी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया है, अक्सर इन अदृश्य खिलाड़ियों द्वारा निर्भाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका को अनदेखा कर दिया है। हालांकि, हाल की वैज्ञानिक प्रगति मिट्टी माइक्रोबायोटम के महत्व पर प्रकाश डाल रही है, जो पौधों के पोषण, रोग प्रतिरोधक क्षमता और समग्र पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव को प्रकट करती है।

मृदा सूक्ष्मजीवों के कार्य: मिट्टी के भीतर मौजूद सूक्ष्मजीवों की विविधता कई आवश्यक कार्य करती है। उदाहरण के लिए, बैक्टीरिया नाइट्रोजन चक्र में मुख्य भूमिका निभाते हैं, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ऐसे रूपों में परिवर्तित करते हैं जिन्हें पौधे अवशोषित कर सकते हैं। कवक, हाइफे के अपने जटिल नेटवर्क के माध्यम से पोषक तत्वों के परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य करते हैं और मिट्टी की संरचना को बढ़ाते हैं। इसके अलावा, वे कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, पौधों के अवशोषण के लिए आवश्यक तत्वों को छोड़ते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव जैव नियंत्रण एजेंट के रूप में भी कार्य कर सकते हैं, हानिकारक रोगजनकों को दबा सकते हैं और सिंथेटिक कीटनाशकों की आवश्यकता को कम कर सकते हैं। अन्य पौधे विकास हार्मोन का उत्पादन करते हैं, जड़ विकास को उत्तेजित करते हैं और पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाते हैं। मृदा माइक्रोबायोटम, संक्षेप में, मिट्टी की उर्वरता और स्वास्थ्य को चलाते वाले जैविक इंजन के रूप में कार्य करता है।

स्वस्थ मृदा माइक्रोबायोटम का महत्व: टिकाऊ कृषि के लिए स्वस्थ और विविधतापूर्ण मृदा माइक्रोबायोटम महत्वपूर्ण है। जब मिट्टी कमजोर या अशांत होती है, तो सूक्ष्मजीव समुदायों का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे मिट्टी की उर्वरता और पौधों के स्वास्थ्य में गिरावट आती है। गहन जुताई, एकल फसल और सिंथेटिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक



उपयोग सभी मिट्टी के माइक्रोबायोटम को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। इस तरह की प्रथाएँ सूक्ष्मजीव विविधता को कम कर सकती हैं, पोषक चक्र को बिगाड़ सकती हैं और बीमारी को दबाने की मिट्टी की क्षमता को कमजोर कर सकती हैं। नतीजतन, पौधे तनाव के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं, बीमारी का प्रकोप अधिक बार होता है और पैदावार कम हो जाती है। स्वस्थ, उत्पादक मिट्टी से जुड़े विशिष्ट सूक्ष्मजीवों को समझना इन महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी प्रणालियों को बहाल करने और बढ़ाने के लिए रणनीति विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

स्वस्थ मृदा माइक्रोबायोटम को बढ़ावा देने वाली प्रथाएँ: ऐसी कई कृषि पद्धतियाँ हैं जो मृदा माइक्रोबायोटम को समृद्ध बना सकती हैं। जुताई को कम करने या खत्म करने से फूँद हाइफे को बिना किसी बाधा के विकसित होने की अनुमति मिलती है, जिससे मृदा संरचना और पोषक तत्वों का बेहतर परिवहन होता है। कवर क्राॉपिंग, फसल चक्रण, और कार्बनिक पदार्थ (जैसे खाद या खाद) का समावेश सूक्ष्मजीवों के लिए भोजन गीत प्रदान करता है और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ाता है। फसलों में विविधता लाने से अधिक विविध माइक्रोबायोटम भी बनता है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र में लचीलापन बढ़ता है। सिंथेटिक कीटनाशकों और उर्वरकों जैसे कठोर रसायनों के उपयोग को कम करना लाभकारी सूक्ष्मजीवों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। पुनर्जो जो कृषि

इन प्रथाओं पर जोर देती है, जिसका उद्देश्य संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है जो प्राकृतिक रूप से पौधों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है।

कृषि का भविष्य और मृदा माइक्रोबायोटम: मृदा माइक्रोबायोटम के महत्व की मान्यता कृषि में प्रतिमान परिवर्तन का प्रतीक है। हम रासायनिक इनपुट पर निर्भरता से आगे बढ़कर एक अधिक समग्र दृष्टिकोण को और बढ़ रहे हैं जो मिट्टी को एक जीवंत, सांस लेने वाली प्रणाली के रूप में देखता है। जैसे-जैसे मृदा माइक्रोबायोटम के बारे में हमारी समझ गहरी होती जाती है, हम अधिक लक्षित और टिकाऊ प्रबंधन पद्धतियाँ विकसित कर सकते हैं। माइक्रोबियल इनोवैयूटेंट (मिट्टी में लाभकारी सूक्ष्मजीवों को शामिल करना) और सटीक कृषि जैसे तकनीकें मृदा स्वास्थ्य को अनुकूलित करने और फसल उत्पादकता बढ़ाने के अवसर प्रदान करती हैं। मृदा माइक्रोबायोटम के साथ साझेदारी में काम करके, हम एक अधिक लचीली, उत्पादक और पर्यावरण को दृष्टि से स्वस्थ कृषि प्रणाली बना सकते हैं। यह दृष्टिकोण दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और हमारे ग्रह के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए महत्वपूर्ण है।

मृदा माइक्रोबायोटम के बारे में कुछ खास बातें: मृदा माइक्रोबायोटम, मिट्टी में कार्बन टर्नओवर और कार्बनिक पदार्थों के स्थिरीकरण में मदद करता है। मृदा माइक्रोबायोटम, मिट्टी की लवणता और अम्लता को भी प्रभावित करता है। मृदा माइक्रोबायोटम, मिट्टी की उर्वरता और फसल के स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। मृदा माइक्रोबायोटम, रोगाणुओं को दबाने में मदद करता है। मृदा माइक्रोबायोटम, पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण में मदद करता है। मृदा माइक्रोबायोटम, मिट्टी की संरचना को सुरक्षित रखता है।

मिट्टी-पौधे सातत्व के साथ माइक्रोबायोटम-आधारित समाधान, और प्रयोगशाला प्रयोगों से लेकर क्षेत्रीय अनुप्रयोगों तक उनका विस्तार, माइक्रोबियल कंसोर्टिया को शक्ति का उपयोग करके कृषि स्थिरता को बढ़ाने का वादा करता है। सिंथेटिक माइक्रोबियल समुदाय, यानी, चर्चित माइक्रोबियल कंसोर्टिया, विशिष्ट कार्य करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इसके विपरीत, प्राकृतिक समुदाय स्वदेशी माइक्रोबियल आबादी का लाभ उठाते हैं जो स्थानीय मिट्टी की स्थितियों के अनुकूल होती हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के लचीलेपन को बढ़ावा देती हैं और बाहरी इनपुट पर निर्भरता को कम करती हैं।

जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक सुस्ती चिंताजनक

हाल में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक-2025 में शीघ्र तीन स्थान का खाली रह जाना यह बोध कराता है कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में कोई भी देश संतोषजनक प्रदर्शन नहीं कर रहा है। यह चिंताजनक है कि सूचकांक की सभी श्रेणियों में किसी भी देश का प्रदर्शन इतना प्रभावी नहीं रहा कि उसे समग्र रूप से 'बहुत उच्च' रेटिंग दी जा सके। इस सूचकांक में डेनमार्क ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, लेकिन उसे चौथा स्थान हासिल हुआ है।

किसी प्रतिभागिता में कोई भी प्रतिभागी प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान प्राप्त नहीं करता है, तो यह स्पष्ट संकेत है कि या तो प्रतिस्पर्धा के मानक बहुत ऊंचे हैं या प्रतिभागियों का प्रदर्शन बेहद कमजोर है। यह सूचकांक वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में असंतोषजनक प्रगति और गैर-जिम्मेदाराना रवैये को उजागर करता है। यह स्थिति दुनिया के देशों को अपनी नीतियों और प्रयासों पर पुनर्विचार करने और अधिक गंभीरता से कार्य करने के लिए प्रेरित भी करती है। इस सूचकांक को पहली बार 2005 में माइंट्रियल में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की 11वाँ बैठक में प्रस्तुत किया गया था। यह सूचकांक पेरिस समझौते (2015) और 2030 तक लक्षित जलवायु परिवर्तन संबंधी लक्ष्यों की प्रगति की दिशा में मूल्यांकन करता है। यह सूचकांक राष्ट्रीय संसदों और सरकारों में बहस को गति देता है। साथ ही, दुनिया के देशों को जलवायु परिवर्तन की दिशा में कार्रवाई के प्रति प्रतिस्पर्धी बनाती है। यह सूचकांक दुनिया के लिए जलवायु परिवर्तन संबंधी प्रगति का आँसू है। यह वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के 90 प्रतिशत से अधिक के लिए जिम्मेदार

उत्सर्जन और ऊर्जा उपयोग श्रेणियों में उच्च रैंकिंग, जलवायु नीति में मध्यम और नवीकरणीय ऊर्जा में निम्न रैंकिंग प्राप्त हुई है। यूनाइटेड किंगडम (छठे) और भारत (10वाँ) सीसीपीआई 2025 में उच्च प्रदर्शन करने वालों में से केवल दो जी-20 देश हैं। चार देश ईरान (67वें स्थान पर), सऊदी अरब (66वें), संयुक्त अरब अमीरात (65वें) और रूस (64वें) स्थान पर है।

सूचकांक रिपोर्ट में जहां केंद्र सरकार की अक्षय ऊर्जा नीति की प्रशंसा की गई है, वहीं कोयले पर निर्भर निरभरता की आलोचना भी की गई है। गौरतलब है कि भारत अक्षय ऊर्जा की दिशा में नित नई ऊंचाई हासिल कर रहा है, जिससे सूचकांक में भारत मजबूत स्थिति में है। गौरतलब है कि जीवाश्म ईंधनों पर अपनी निरभरता घटाने के लिए भारत कई मोर्चों पर आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार ने सीओ-26 सम्मेलन में घोषित 'पंचमृत' की श्रेणी के तहत 2030 तक गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक ले जाने, अपनी ऊर्जा जरूरतों का 50 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त करने, कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में एक अरब टन की कमी करने, अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45 प्रतिशत से कम करने तथा 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में प्रतिबद्धता से जुटी है।

सतत विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश में नवीकरणीय (अक्षय) ऊर्जा के विकास पर पयास ध्यान दिया जा रहा है। भारत की भौगोलिक दशाएँ भी नवीकरणीय ऊर्जा के लिए वृहत संभावना का द्वार खोलती हैं। प्राकृतिक रूप से भारत अक्षय ऊर्जा के मामले में अत्यंत धनी देश रहा है। उष्णकटिबंधीय जलवायु होने के कारण भारत में सौर ऊर्जा और विशाल समुद्री तटीय क्षेत्र होने के कारण पवन और ज्वारीय तरंगों की प्रबलता के कारण ज्वारीय ऊर्जा तथा कृषि एवं पशुपालन का लंबा इतिहास होने के कारण बायोगैस जैसे अक्षय ऊर्जा के विविध स्वरूपों के विकास की अपार संभावनाएँ हैं।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार, देश की कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता 10 अक्टूबर, 2024 को 200 गीगावाट (गीगावाट) के आंकड़े को पार कर गई है। यह उपलब्ध इसलिए भी खास है कि भारत की कुल बिजली उत्पादन क्षमता 452.69 गीगावाट है, जिसमें लगभग आधी हिस्सेदारी अक्षय ऊर्जा स्रोतों की हो गई है। अक्षय ऊर्जा के मामले में सौर ऊर्जा देश में पहले स्थान पर है। देश में सौर ऊर्जा का उत्पादन 90.76 गीगावाट तक हो रहा है। भारत में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएँ हैं। देश में साल के लगभग तीन सौ दिन अच्छी धूप पड़ती है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी की सतह पर एक से डेढ़ घंटे के दौरान पड़ने वाली सूरज की रोशनी को अगर ऊर्जा में तब्दील कर दिया जाए, तो इससे दुनियाभर में एक साल में खपत होने वाली ऊर्जा मांग की पूर्ति हो सकती है।



63 देशों और यूरोपीय संघ के देशों के जलवायु परिवर्तन के संबंध में किए जा रहे प्रयासों पर आधारित है। सूचकांक के मूल्यांकन के लिए चार आधारों का उपयोग किया जाता है, जिसमें प्रति व्यक्ति ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा की प्रगति, प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपयोग और जलवायु नीति शामिल हैं। इस वैश्विक सूचकांक का मुख्य उद्देश्य विभिन्न देशों द्वारा जलवायु संकेत के न्यूनिकरण की दिशा में उन्नत जाने वाले प्रयासों का आकलन करना है। हालांकि, सूचकांक के इस 20वें संस्करण से बोध होता है कि किसी भी देश ने जलवायु परिवर्तन संबंधी इस दिशा में पयास और उच्छेद कार्य नहीं किया है। जाहिर है, विश्व स्तर पर जलवायु परिवर्तन के खतरे से भलीभांति परिचित होने के बावजूद इस गंभीर मुद्दे को लेकर प्रतिबद्धता और प्रयासों में भारी कमी है। सूचकांक में डेनमार्क, नीदरलैंड और यूनाइटेड किंगडम इस वषड़ अग्रणी रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े उत्सर्जक देशों जैसे चीन और अमेरिका का प्रदर्शन बहुत निम्न श्रेणी में रखा गया है। हालांकि इस सूचकांक में भारत का प्रदर्शन संतोषजनक रहा है। इसमें भारत 10वें स्थान पर है, जो सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाले देशों में से एक है। पिछले वर्ष भारत सातवें स्थान पर था। भारत को ग्रीनहाउस गैस

विश्व दलहन दिवस: पोषक तत्व, स्वस्थ आहार और टिकाऊ खेती के लिए अहम है दालें

हर साल 10 फरवरी को हम विश्व दलहन दिवस मनाते हैं, जो दालों के महत्व और पोषण संबंधी फायदों को और ध्यान आकर्षित करता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त यह दिन इन आश्चर्यकृत खाद्य पदार्थों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। यह दालों से मिलने वाले पोषण, खाद्य सुरक्षा और पर्यावरणीय फायदों पर भी जोर देता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, यह दिन विविधकरण के लिए इसके स्थायी विकल्प की भूमिका को उजागर करने का अवसर प्रदान करता है। दालें, जिन्हें अम्लीय पर फलिया के रूप में जाना जाता है, खाने के लिए आगए जाने वाले फलीदार पौधों के बीज होते हैं। विभिन्न प्रकारों में, सूखी फलियाएँ, दालें और मटर सबसे लोकप्रिय हैं। साल 2013 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव (ए/आरएस/एस/68/231) पारित किया, जिसमें 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष के रूप में मान्यता दी गई। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) के नेतृत्व में, इसे दालों के पोषण और पर्यावरणीय लाभों के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। हालांकि इसकी शानदार सफलता के बाद, सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा को हासिल करने के लिए फसलों की क्षमता को मान्यता दी गई। विशेष रूप से, सतत विकास लक्ष्य एक, दो, तीन, पांच, आठ, 12, 13 और 15 को प्रोत्साहित दी गई। इसके कारण कुर्छिना फसलों में विश्व दलहन दिवस मनाया जा सकता है। बाद में 2019 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। इस साल विश्व दलहन दिवस की थीम है दालें: कृषि-खाद्य प्रणालियों में विविधता लाना। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2016 को दलहन वर्ष घोषित किया था, जिसका उद्देश्य दालों के उत्पादन के साथ-साथ उनकी खपत को बेहतर बनाना था, खास तौर पर दुनिया के उन हिस्सों में जहाँ पोषक तत्वों की कमी के कारण टाइप-टू डायबिटीज एक बड़ी समस्या के रूप में उभरी है। विश्व दलहन दिवस शरीर उद्देश्य से अरिस्तव में आया। बहुत ज्यादा पोषण के लिए जानी जाने वाली दालें शरीर के कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने और रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में सबसे अच्छा काम करती हैं। यह माटोमो से लड़ने और कई गैर-संचारी रोगों के प्रबंधन में भी मदद कर सकती है।

यह दिन दलहन फसलों के महत्व, विशेष रूप से उनके पोषण, खाद्य सुरक्षा और पर्यावरणीय फायदों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। इसका उद्देश्य मानव स्वास्थ्य और मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करने में इसकी भूमिका के कारण दालों की खेती को बढ़ावा देना है।

मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना की अनुदान व्यवस्था को सरकार ने किया संशोधित

किसानों को अब खेत में सोलर पम्प लगाने देना होगा मात्र 10% राशि

भोपाल। जागत गांव हमार

किसानों को वर्ष भर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही खेती की लागत को कम करने के लिए सरकार द्वारा सोलर पम्प को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों के द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इस कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार ने किसान हित में बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में महेश्वर में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश में कृषक/कृषकों के समूह को कृषि पम्प कनेक्शन प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना में वर्तमान में प्रचलित मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना अंतर्गत सोलर कृषि पम्प भी सम्मिलित किए जाने का निर्णय लिया है।



किसानों को सोलर पम्प के लिए दिन होगा मात्र 10 प्रतिशत राशि

मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना की अनुदान व्यवस्था को संशोधित किया गया है। अब योजना में परियोजना लागत का श्रेणीवार 5 प्रतिशत अथवा 10 प्रतिशत कृषक द्वारा मॉर्निंग मनी के रूप में दिया जाएगा। शेष राशि के लिए कृषक द्वारा ऋण लिया जाएगा, जिस ऋण के भुगतान का संपूर्ण दायित्व राज्य शासन का होगा यात्रि की किसान द्वारा जो ऋण लिया जाएगा उसका भुगतान सरकार करेगी।

सरकार देगी शेष राशि

योजना के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शेष ऋण का भुगतान सोलर कृषि पंप लगाने की वजह से कृषि उपभोक्ताओं के लिए अटल कृषि ज्योति योजना एवं अन्य योजनाओं के अंतर्गत वितरण कंपनियों को देय सब्सिडी में हुई बचत से ऋण का भुगतान किया जा सकेगा। योजना के प्रथम चरण में अस्थायी विद्युत संयोजन वाले उपभोक्ताओं अथवा अविद्युतिकृत कृषकों को सोलर पंप का लाभ दिया जाएगा। योजना के आगामी चरणों में स्थायी विद्युत पंप उपयोग कर रहे कृषकों को भी सोलर पंप दिया जाना प्रस्तावित है। इसका क्रियान्वयन राज्य में मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम द्वारा केन्द्र सरकार की कुसुम योजना के घटक 'ब' अंतर्गत किया जाएगा। सोलर पम्प की स्थापना से विद्युत पम्पों को विद्युत प्रदाय के लिए राज्य सरकार पर अनुदान के भार को सीमित किया जा सकेगा एवं विद्युत वितरण कम्पनियों की वितरण हानियों को भी कम किया जा सकेगा।

किसानों को मिलेगा बेहतर बाजार

अब फल-फूल और सब्जी फसलों के लिए अलग से बनाई जाएगी मंडी

भोपाल। जागत गांव हमार

देश में किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उद्यानिकी फसलों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे में किसानों को अपने उत्पाद बेचने के लिए बेहतर बाजार मिल सके इसके लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। इस कड़ी में मध्य प्रदेश में उद्यानिकी फसलों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उद्यानिकी फसलों के लिए पृथक उद्यानिकी उपज मंडी बनाई जाएगी। राज्य शासन द्वारा लिए गये निर्णय पर अमल के लिए उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा की अध्यक्षता में उद्यानिकी बोर्ड की बैठक की गई।



किसान सीधे कर सकेंगे अपनी फसल की विक्री

मंत्री कुशवाहा ने निर्देश दिए कि संचालक उद्यानिकी, प्रबंध संचालक मंडी बोर्ड प्रबंध संचालक एमपी एग्री एवं विशेषज्ञों की टीम एक माह में विस्तृत सर्वे कर सलाहकार बोर्ड के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी। उद्यानिकी मंत्री ने कहा यह उद्यानिकी उपज मंडी पूर्णतः हाईटेक होगी, जिनमें फसल उत्पादक किसान सीधा उपभोक्ताओं को अपनी फसल का विक्रय कर सकेंगे। यह व्यवस्था बिचौलियों से मुक्त होगी।

अभी फल और सब्जियों के लिए है 174 मंडी

वर्तमान में मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के अधीन मग्न राज्य कृषि विपणन बोर्ड का गठन किया गया है। इनमें कृषि और उद्यानिकी का फसलों का क्रय-विक्रय एक ही परिसर में किया जाता है। प्रदेश की 25, कृषि उपज मंडी समिति है इनमें फल-सब्जियों के विक्रय के लिये 174 मंडियां अधिसूचित है। नवीन व्यवस्था लागू हो जाने पर फल-फूल, सब्जी फसल के लिए पृथक नवीन परिसर बनाये जाएंगे। प्रस्तावित मंडियों में ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, पैकिंग, पैक हाउस, कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चैन, भंडारण आदि सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

यहां से होगी शुरुआत- उद्यानिकी बोर्ड की बैठक में मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने कहा कि उद्यानिकी फसलों के उत्पादक कृषकों को उनकी फसल का उचित दाम दिलाने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा पृथक से उद्यानिकी फसल उपज मंडी बोर्ड बनाने पर कार्य प्रारंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की ऐसी प्रमुख 11 कृषि उपज मंडी इंदौर, बुधनापुर, शाजापुर, मंदसौर, उज्जैन, बदनावर, रतलाम, नीमच, भोपाल, जावरा और शुजालपुर, जिनमें एक लाख टन से अधिक उद्यानिकी फसलों की आवक होती है, ऐसी मंडियों में प्रथम चरण में बोर्ड बनाकर उद्यानिकी फसलों के विक्रय के लिए पृथक से परिसर बनेगा।

बलराम तालाब योजना

75 प्रतिशत अनुदान पर सरकार बनवाएगी 6144 तालाब, सिंचाई की समस्या का होगा समाधान

भोपाल। जागत गांव हमार

किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए साल भर पानी मिल सके इसके लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं, इसमें खेतों में तालाब का निर्माण, नहरों का निर्माण, नलकूपों का निर्माण आदि शामिल है। इसके लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इस कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में बलराम तालाब योजना चलाई जा रही है। योजना के तहत किसानों को खेत में तालाब बनाने के लिए 75 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जाता है।



इस साल बनाए जाएंगे 6144 तालाब

राज्य में बलराम तालाब योजना के तहत वित्त वर्ष 2023-24 में 569.30 लाख रुपए की राशि से 662 बलराम तालाब निर्मित किए गए थे। जबकि विभाग द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए 5308.34 रुपए का वित्तीय लक्ष्य एवं 6144 बलराम तालाब निर्मित किये जाने का भौतिक लक्ष्य रखा गया है। बलराम तालाब योजना का लाभ लेने के लिए किसान ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। साथ ही योजना की अधिक जानकारी के लिए किसान अपने ब्लॉक या जिले के कृषि विभाग में संपर्क कर सकते हैं।

बलराम तालाब योजना के तहत कितना अनुदान मिलता है- कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही बलराम तालाब योजना में सामान्य किसानों को स्वयं के व्यय पर तालाब निर्माण करने पर लागत राशि का 40 प्रतिशत अधिकतम 80 हजार रुपए का अनुदान मिलता है। योजना में लघु-सीमान्त कृषकों को लागत राशि का 50 प्रतिशत और अधिकतम 80 हजार रुपए और अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों को लागत राशि का 75 प्रतिशत अधिकतम एक लाख रुपए की अनुदान राशि दिए जाने का प्रावधान है।

मध्यप्रदेश को वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 में अवॉर्ड से भी किया गया सम्मानित

एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड: किसानों को बैंक लोन पर तीन फीसदी छूट

भोपाल। जागत गांव हमार

देश में कृषि क्षेत्र के विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के सृजन के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना चलाई जा रही है। योजना का उद्देश्य देश में कृषि अवसंरचना का विकास एवं विस्तार करना है। इस योजना के माध्यम से कृषक, कृषि अवसंरचना निर्माण के लिये बैंक से प्राप्त राशि 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर तीन प्रतिशत व्याज छूट का लाभ सात वर्षों के लिए ले सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत किसान वेयरहाउस, साइलॉस, कस्टम हायरिंग सेंटर, कोल्ड स्टोरेज, सॉर्टिंग व ग्रेडिंग इकाई, प्राथमिक प्र-संस्करण इकाई, एगरोपोनिक फार्मिंग, हायड्रोपोनिक फार्मिंग, वर्टिकल फार्मिंग, मशरूम फार्मिंग, स्मार्ट प्रिसीजन फार्मिंग के लिये अवसंरचना का निर्माण कर सकते हैं।



मध्यप्रदेश में किसानों ने लगाए सबसे अधिक प्रोजेक्ट

एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के तहत मध्य प्रदेश को वर्ष 2025-26 तक 7440 करोड़ रुपये का लक्ष्य दिया गया है। जिसके विरुद्ध 7,804 करोड़ रुपए के कुल 10,860 प्रकरण स्वीकृत किए जा चुके हैं, जो कि देश के सभी राज्यों में सर्वाधिक है। इसके अतिरिक्त कुल 10,047 प्रकरणों में 5978 करोड़ रुपए का डिसबर्समेंट किया जा चुका है जो अन्य राज्यों की अपेक्षा कहीं अधिक है। केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में मध्यप्रदेश को 500 करोड़ रुपए का लक्ष्य दिया गया था जिसके विरुद्ध 1240 करोड़ रुपए के कुल 2152 प्रकरण स्वीकृत किए जा चुके हैं, जो कि आवंटित लक्ष्य का 248 प्रतिशत है। साथ ही कुल 1745 प्रकरणों में 721 करोड़ रुपए का डिसबर्समेंट किया जा चुका है। केन्द्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का देश में सर्वोत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए मध्यप्रदेश को वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में अवॉर्ड से सम्मानित भी किया गया है।



भोपाल। आज खेती के काम को व्यवसाय की दृष्टि से देखा जाने लगा है। ऐसे में किसानों को भी चाहिए कि वे बाजार की मांग और उससे होने वाले मुनाफे को देखकर खेती करें, जिससे उन्हें बेहतर लाभ मिल सके। किसानों को फरवरी माह में बोई जाने वाली इन सब्जियों की खेती की जानकारी दे रहे हैं जिससे वे काफी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, तो आइए जानते हैं इसके बारे में...।

खीरा की बाजार मांग को देखते हुए इसकी खेती मुनाफे का सौदा

किसानों के फायदेमंद हो सकती है फरवरी माह में इन सब्जियों की खेती

करेला की उन्नत खेती दे सकती है अच्छा लाभ

करेला विशेष कर शगर व डायबिटीज के रोगियों के लिए काफी अच्छा माना जाता है। इसकी बाजार मांग भी काफी अच्छी रहती है और इसके भाव भी बेहतर मिल जाते हैं ऐसे में इसकी खेती की जाए तो किसान इससे काफी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। एक अनुमान के मुताबिक करेले की खेती की एक एकड़ में लागत 50-60

हजार रुपए तक आती है। इस तरह देखा जाए तो किसान इसकी खेती करके काफी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसकी खेती के लिए हाइब्रिड किस्में काफी अच्छी मानी गई हैं। करेले की हाइब्रिड किस्मों में पूसा हाइब्रिड 1, पूसा हाइब्रिड 2 काफी अच्छी मानी जाती है। इसकी अन्य बेहतर किस्मों में पूसा विशेष, अर्का हरित, पंजाब करेला 1 आदि शामिल हैं।

हजार रुपए तक आती है। इस तरह देखा जाए तो किसान इसकी खेती करके काफी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसकी खेती के लिए हाइब्रिड किस्में काफी अच्छी मानी गई हैं। करेले की हाइब्रिड किस्मों में पूसा हाइब्रिड 1, पूसा हाइब्रिड 2 काफी अच्छी मानी जाती है। इसकी अन्य बेहतर किस्मों में पूसा विशेष, अर्का हरित, पंजाब करेला 1 आदि शामिल हैं।

तोरई की खेती में भी होगा फायदा

फरवरी माह में तोरई की खेती से भी काफी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। इसकी बाजार मांग भी काफी अच्छी रहती है। तोरई में कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं जिसमें

आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए, सी और बी पाया जाता है जो सेहत के लिए काफी फायदेमंद होते हैं।

किसान इसकी पूसा चिकनी, पूसा खेहा, पूसा सुप्रिया, काशी दिव्या, कल्याणपुर चिकनी, फुले प्रजतका आदि उन्नत किस्मों की बुवाई करके इससे काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बता दें कि तोरई की उन्नत किस्मों के बीज रोपाई के बाद 70 से 80 दिन में फल देना शुरू कर देते हैं। यह किस्में 150 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से पैदावार देती हैं।

ककड़ी की खेती और उन्नत किस्में

ककड़ी की फसल एक तरह से नकदी फसल के तौर पर जानी जाती है। इसकी खेती करके किसान अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसकी खेती के लिए कई हाइब्रिड किस्में हैं जो बेहतर उत्पादन देती हैं जिनमें जैनपुरी ककड़ी, अर्का शीतल, पंजाब स्पेशल, दुर्गापुरी ककड़ी, लखनऊ अर्ली आदि ऐसी किस्में हैं जो बेहतर पैदावार देती हैं। खास बात ये हैं कि ककड़ी की इन

प्रजातियों के फल 60 से लेकर 70 दिन बाद ही तुड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। अनुमान के तौर पर देखें तो ककड़ी की एक हेक्टेयर में खेती से किसान 200-250 किलो तक पैदावार प्राप्त कर सकते हैं।

खीरा की उन्नत किस्में और इसकी खेती के लाभ

खीरा की बाजार मांग को देखते हुए इसकी खेती किसानों के लिए मुनाफे का सौदा साबित हो रही है। खीरे की कई उन्नत किस्में हैं खीरा की खेती करके किसान काफी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसकी भारतीय किस्मों में स्वर्ण अंगती, स्वर्ण पृष्णिन्ना, पूसा उदय, पूना खीरा, पंजाब सलेक्शन, पूसा संयोग, पूसा बरखा,

खीरा 90, कल्याणपुर हरा खीरा, कल्याणपुर मध्यम और खीरा 75 आदि आती हैं। वहीं इसकी नवीनतम किस्मों में पीसीयूएच-1, पूसा उदय, स्वर्ण पूर्णा और स्वर्ण शीतल आदि प्रमुख हैं। इसके अलावा इसकी संकर किस्मों में पंत संकर खीरा-1, प्रिया, हाइब्रिड-1 और हाइब्रिड-2 आदि हैं। इसकी विदेशी किस्में भी अच्छा मुनाफा देती हैं जिनमें जापानी लॉग ग्रीन, चयन, स्ट्रेट-8 और पोइनसेट किस्में काफी अच्छी मानी जाती हैं। अच्छी प्रजाति के बीज इस्तेमाल करने पर यह बुवाई के करीब दो माह बाद फल देने लगते हैं। इसकी अनुमानित उपज 50-60 किलो प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त की जा सकती है।

पालक की उन्नत किस्में और इसकी खेती के लाभ

पालक में आयरन की प्रचुर मात्रा होती है। सेहत के लिए पालक का सेवन काफी अच्छा माना गया है। इसकी बाजार में डिमांड रहती है। पालक की अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों में आल ग्रीन, पूसा हरित, पूसा ज्योति, बनजी जाईट, जोबनेर ग्रीन आती हैं। इनकी खेती करके किसान प्रति हेक्टेयर 80 से लेकर 90 किलो तक हरी पत्तियों के रूप में उपज प्राप्त कर सकते हैं।

लौकी की उन्नत किस्में और इसकी खेती के लाभ

लौकी की खेती से भी किसान काफी अच्छी इनकम कर सकते हैं। इसकी खेती के लिए अर्का नूतन, अर्का श्रेयस, पूसा संतुष्टि, पूसा संदेश, अर्का गंगा, अर्का बहार, पूसा नवीन, पूसा हाइब्रिड 3, सम्राट, काशी बहार, काशी कुंडल, काशी कीर्ति एंव काशी गंगा आदि किस्में बेहतर पैदावार देने वाली किस्में हैं। वहीं इसकी हाइब्रिड किस्में भी अच्छा उत्पादन देती हैं जिनमें काशी बहार, पूसा हाइब्रिड 3, और अर्का गंगा आदि लौकी की हाइब्रिड किस्में शामिल हैं। इसकी उन्नत किस्में 50-55

दिनों में तैयार हो जाती है। इन किस्मों से औसत उपज 32 से 58 टन प्रति हेक्टेयर के आसपास तक प्राप्त की जा सकती है। इसकी एक एकड़ में बुवाई की लागत 15 से 20 हजार रुपए तक आती है। बाजार भाव अच्छा मिल जाने पर इससे करीब 80 हजार से लेकर एक लाख तक की आय प्राप्त की जा सकती है।

बैंगन की उन्नत किस्में और इसकी खेती के लाभ

बैंगन की खेती करके भी किसान इससे अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बैंगन की उन्नत किस्मों में पूसा पपचर लॉग, पूसा पर्पर कलस्टर, पूसा हायब्रिड 5, पूसा पर्पर राउंड, पंत रितूरान, पूसा हाइब्रिड-6, पूसा अनमोल आदि शामिल हैं। इसका एक हेक्टेयर में करीब 450 से 500 ग्राम बीज डालने पर करीब 300-400 किलो प्रति हेक्टेयर तक का उत्पादन मिल जाता है।

भिंडी की उन्नत किस्में और इसकी खेती के लाभ

भिंडी की फसल दो से ढाई महीने के बाद ही तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है और इसकी बाजार मांग भी अच्छी रहती है। इसकी उन्नत किस्मों में परभन क्रांति, पूसा सावनी, पंजाब पचनी, पूसा ए-4, अर्का भय, अर्का अनामिका, पंजाब-7, पंजाब-13 अच्छी मानी जाती है। इसकी अन्य किस्मों में वर्षा, उपहार, वैशाली, लाल हाइब्रिड, ईएमएस-8 (म्यूटेंट), वर्षा, विजय, विशाल आदि शामिल हैं। भिंडी की खेती से किसान प्रति हेक्टेयर 115-125 किलो तक की पैदावार प्राप्त कर सकते हैं।

फूलगोभी की उन्नत किस्में और इसकी खेती के लाभ

फूल गोभी में प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए, सी तथा निकोटीनिक एसिड जैसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभकारी होते हैं। इसके सेवन करने से पाचन शक्ति मजबूत होती है तथा कैंसर जैसे रोगों की रोकथाम में भी मदद मिलती है। किसान भाई इसकी खेती करके बेहतर लाभ कमा सकते हैं।

इसकी अंगेती किस्मों में अर्ली, कुंआरी, पूसा कालिका, पूसा दीपाली, समर किंग अच्छी उपज देने वाली किस्में

मानी जाती है। पछेली किस्मों में इसकी पूसा शोबाल-1, पूसा शोबाल-2, पूसा शोबाल-16 किस्में अच्छी हैं। इसके अलावा इसकी मध्यम किस्मों में पंत सुधा, पूसा सुधा, पूसा सिन्थेटिक, पूसा अगहनी, पूसा शोबाल किस्में बेहतर उत्पादन देने वाली किस्में हैं।

अरबी की उन्नत किस्में और इसकी खेती के लाभ

अरबी की खेती भी किसानों के लिए काफी लाभकारी साबित हो रही है। इसकी कई किस्में हैं जो अधिक उत्पादन देती हैं जिनमें पंचमुखी, सफेद गौरिया, सहमुखी, सी-9, सलेक्शन प्रमुख हैं।

इसके अलावा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित इंदिरा अरबी -1 और नरेंद्र अरबी-1 किस्म भी

अच्छा उत्पादन देती है। यदि उन्नत तरीके से इसकी खेती की जाए तो इससे 150 से 180 किलो प्रति हेक्टेयर तक उपज प्राप्त की जा सकती है। इसका भाव बाजार में अच्छा भाव मिल जाता है। यदि भाव बेहतर मिल जाए तो अरबी से आप प्रति एकड़ 1.5 से 2 लाख रुपए तक की कमाई कर सकते हैं।

मध्यप्रदेश के तीन गांवों को मिल चुका केंद्र सरकार से सम्मान

इंवेस्टर समित के उद्यमियों को घुमाएंगे पर्यटन ग्राम खारी

ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देगी मोहन सरकार प्रदेश में 100 नए होम स्टे बनाने की तैयारी

भोपाल। जगत गांव हमार

मप्र सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगाता प्रयासरत है। कोरोना महामारी के बाद पर्यटकों में ग्रामीण पर्यटन की तरफ झुकाव देखने को लि रहा है, जिसे देखते हुए मोहन सरकार प्रदेश में होस्टे को विस्तार देने की योजना पर काम कर रही है। इसी के तहत प्रदेश में 100 नए होम स्टे जोड़ने की योजना पर काम चल रहा है, जिसके तहत 100 गांवों को चिन्हित किए जाएंगे। जिन्हें होम स्टे के हिसाब से डेवलप किया जाएगा, ताकि पर्यटकों को ग्रामीण पर्यटन का आनंद मिल सके और ग्रामीणों को रोजगार।

भोपाल में इसी महीने की 24 और 25 फरवरी को आयोजित इंवेस्टर्स समित में उद्यमियों को टूरिस्ट विलेज घुमाने की योजना भी है। इसके लिए भोपाल और सीहोर बाईर पर बसे खारी गांव को चुना गया है। यहाँ कुल सात ग्रामीणों ने अपने घर को विलेज टूरिज्म के अंतर्गत होम स्टे में तब्दील किया है। इस गांव की दूरी भोपाल से सबसे कम है। इसके अलावा भोपाल की अन्य 55 डेस्टिनेशन हैं और इनमें से एकदम ट्रेडिशनल तरीके से बने हुए होम स्टे पहली प्राथमिकता में है। इनमें खारी गांव का गिरिजा होम, बसंत होम स्टे, बेरी हाइडआउट, कोजी हेविन, जयंशी होम स्टे प्रमुख हैं। यह सभी एकदम देसी अंदाज वाले मकान हैं।



मध्य प्रदेश में अभी 321 होम स्टे

बता दें कि मध्य प्रदेश में अब तक होम स्टे के लिए पूरे प्रदेश में 321 गांवों को होम स्टे के हिसाब से बनाया गया है, 100 नए गांव और जुड़ जाने से प्रदेश में होम स्टे की संख्या 425 हो जाएगी।

उज्जैन में 78, भोपाल में 59 और इंदौर में हैं 30 होम स्टे

उज्जैन - 78, भोपाल - 59, इंदौर - 30, ओरछा- 29, खजुराहो - 22, कान्हा नेशनल पार्क 18, पचमढ़ी 12, जबलपुर 11, पंच नेशनल पार्क - 9, लाडपुरा खास - 5, मितावली पड़वली - 5, धमना बस्ता - 5, खाखरा थड़ीपत्थर - 7, साबरवानी - 4, ग्वालियर - 7, पन्ना नेशनल पार्क - 10, सतना मैहर - 5, महेश्वर - 5

जल-जंगल जमीन

पर्यटन विभाग ऐसे 100 गांवों को चिन्हित करेगा, जहाँ जल-जंगल जमीन सबकुछ होगा। इसके लिए तीन कैटेगरी बनाई गई हैं, जिसमें होम स्टे, फार्म स्टे और ग्राम स्टे को शामिल किया जाएगा। इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं, जिसके लिए आवेदन बुलाए जा रहे हैं।

ये सुविधा मिलेगी

जिन गांवों में होम स्टे की सुविधा दी जाएगी, उनके आसपास जंगल होगा, खेत में बीचों बीच घर बना होगा, इसके अलावा जहाँ पर्यटकों की सुरक्षा और निजता का पूरा ध्यान रखा जाएगा, ताकि पर्यटकों को शांति का अनुभव हो।

ग्रामीण जीवन

पर्यटकों को यहाँ पूरी तरह से ग्रामीण जीवन शैली जीने का मौका मिलेगा, जहाँ देसी खाना, बैलगाड़ी, गांव खलिहान में भ्रमण, अकाउंटिंग, हाउसकीपिंग, गेस्ट हाउस प्रबंधन के साथ-साथ फोटोग्राफी का भी मजा होगा।

ये गांव हैं बैस्ट

मध्य प्रदेश के तीन गांव प्राणपुर, साबरवानी और लाडपुरा होम स्टे के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम के रूप में केंद्र सरकार की तरफ से सम्मानित भी किया जा चुके हैं। खास बात यह है कि इन गांवों का सिलेक्शन देश के 900 गांवों में से हुआ था। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश में पर्यटन की वजह से कई रोजगार मिलते हैं, ऐसे में 100 नए गांव और होम स्टे में जुड़ने से लोगों को रोजगार भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ होम स्टे के लिए स्थानीय लोगों के घरों को ही डेवलप किया जाता है।

प्रकृति के साथ-साथ बुंदेली संस्कृति का आनंद

ओरछा के लाडपुरा में पहुंच रहे देश-विदेश से पर्यटक, यहां सर्दी-गर्मी भी बेअसर

पर्यटन बोर्ड की अपर प्रबंध संचालक ने 6 का किया शुभारंभ नर्मदापुरम के मढ़ई पर्यटन स्थल के समीप बन रही 15 होमस्टे



निवाड़ी। जगत गांव हमार

ओरछा देश-विदेश से पर्यटक यहाँ आते हैं और स्टे भी करते हैं। इस बीच ओरछा के पास स्थित लाडपुरा गांव ने विश्व पर्यटन के मानचित्र में अपनी जगह बना ली है। यहाँ शानदार होम स्टे बनाए गए हैं, जिसमें गांव का परिदृश्य दिखाता है। देश-विदेश से आने वाले पर्यटक यहाँ रुकते हैं और प्रकृति के साथ-साथ बुंदेली संस्कृति का आनंद लेते हैं।

3 से 14 हुई होम स्टे की संख्या- जानकारी के अनुसार 4 वर्ष पूर्व पर्यटन विभाग के सहयोग से स्थानीय लोगों ने होम स्टे कार्य प्रारंभ किया था। शुरुआती दौर में यहाँ 3 होम स्टे हुआ करते थे, लेकिन आज इनकी संख्या बढ़कर करीब 14 हो गई है। बुंदेलखंड के गांव जैसा माहौल बनाने के लिए गांव में ही इन

कमरों को बनाया गया है। कमरे की छत पर मिट्टी का खपरैल लगाया गया है। कमरों के बाहर गाय के गोबर से लीपा जाता है।

लाडपुरा गांव का खपरैल होम स्टे- यहाँ कमरों के आसपास स्थित खेतों में लहलहाती फसलों को देखकर सैलानी ग्रामीण परिवेश का पूरा लुत्फलेते हैं। होम स्टे संचालिका सीमा कुशवाहा बताती हैं कि इन कमरों की बनावट कुछ ऐसी है कि मौसम कोई भी हो, सर्दी हो या गर्मी, कमरे में इसका असर नहीं होता है। कमरे के अंदर एक बेड रहता है, इसके साथ ही कमरे की छत किसी ग्रामीण क्षेत्र में होने का एहसास देती है। यहाँ आने वाले सैलानी अपने इन पलों को हमेशा याद रखते हैं और वे अपने परिवार और मित्रों को भी यहाँ आने की सलाह देते हैं।

बुंदेली भोजन को बड़े चाव से खाते हैं सैलानी

सैलानियों के होम स्टे में रुकने के दौरान यहाँ उन्हें सुबह का नाश्ता और दोपहर व रात को बुंदेली भोजन परोसा जाता है। जिसमें कढ़ी, चावल रोटी, चीला, पत्थर के सिलबट्टी की चटनी, मट्ठे का रायता, बेसन का मेड़ा, दाल, बँगन का भर्ता, गुलगुला इत्यादि विभिन्न प्रकार के बुंदेली भोजन शामिल होते हैं। होम स्टे संचालिका सीमा बताती हैं कि देश के कोने-कोने से आए लोग यहाँ ग्रामीण परिवेश में रहकर बड़े प्रसन्नचित होते हैं। रसोई में बुंदेली भोजन बनाते समय कई सैलानी रसोई में उनका सहयोग भी करते हैं, जिसमें सैलानियों को बड़ा आनंद आता है।

नर्मदापुरम। जगत गांव हमार

नर्मदापुरम के मढ़ई पर्यटन स्थल के नजदीक बन रही 15 होमस्टे में से बनकर तैयार हो गए हैं, जहाँ अब पर्यटक विलेज लाइफ का एक्सपीरियंस ले सकेंगे। ये होम स्टे ग्राम छेड़का, ढाबा और उरदौन में बनकर तैयार हुए हैं। बसंत पंचमी पर्व पर मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड की अपर प्रबंध संचालक विदिशा मुखर्जी ने ग्राम छेड़का में बने 06 होमस्टे का शुभारंभ किया।

होमस्टे के साथ लें विलेज लाइफका मजा- मढ़ई को पास ग्राम छेड़का और ढाबा में बने होम स्टे में पर्यटक ग्रामीण जीवन का अनुभव कर सकेंगे। बेहद किफायती दरों पर यहाँ ठहरने की व्यवस्था के साथ स्थानीय व्यंजन का भी मजा ले सकेंगे। इसके साथ ही

टूरिज्म बोर्ड की एएमडी ने किया आदिवासी नृत्य

होम स्टे के उद्घाटन अवसर पर ग्रामीणों द्वारा शानदार सैतम और डंडा नृत्य प्रस्तुत किया गया, जिसमें पर्यटन बोर्ड की एएमडी विदिशा मुखर्जी ने भी स्थानीय महिलाओं के साथ नृत्य किया। इसके बाद उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त महिला ड्राइवर्स की जिप्सी में की जंगल की सैर की।

यहाँ बैलगाड़ी की सवारी, जनजातीय सैतम और डंडा नृत्य, गोंड पेंटिंग, मड आर्ट, जिप्सी राइड और लजीज स्थानीय व्यंजनों का मजा भी मिलेगा।



-कृषक जीवन कल्याण योजना में 4 लाख की सहायता

मध्यप्रदेश की मोहन सरकार की प्राथमिकता में अन्नदाता

भोपाल। जागत गांव हमार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार निरंतर किसानों के कल्याण के लिए कृत संपत्त्य होकर कार्य कर रही है। सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ज्ञान से ध्यान पर फोकस करते हुए चार मिशन के क्रियान्वयन पर जोर दिया है। जल्द ही प्रदेश में किसान कल्याण के लिए मिशन भी प्रारंभ होने वाला है। वर्तमान में किसानों के कल्याण की विभिन्न योजनाएं संचालित हो रही है। प्रदेश के कृषकों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना लागू की गई है। योजनांतर्गत कृषकों को आंशिक अपंगता के लिये 50 हजार रुपए की सहायता प्रदान की जाती है। स्थायी अपंगता पर एक लाख और मौत होने पर 4 लाख प्रदान किए जाते हैं। साथ ही अंत्येष्टि के लिए 4 हजार की सहायता दिए जाने का प्रावधान है।



तुलावटी वृद्धावस्था

प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों में कार्यरत अनुसूचितधारी हममल एवं तुलावटीयों के सहायताार्थ मुख्यमंत्री कृषि उपज मंडी हममल एवं तुलावटी वृद्धावस्था सहायता योजना-2015 लागू की गई। यह योजना उन हममल एवं तुलावटीयों एवं उनके परिवार के अधिकतम सदस्यों पर प्रभावी होगी, जो मंडी उपस्थिति के प्राधान्य अनुसार मंडी समिति में 18 से 55 वर्ष आयु के अनुसूचितधारी हममल एवं तुलावटी हैं। योजनांतर्गत हितग्राही को वृत्तमान एक हजार एवं अधिकतम 2 हजार तक प्रति वर्ष अंशदान जमा करना होगा। योजना का लाभ पात्रता रखने वाले अनुसूचितधारी हममल एवं तुलावटीयों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण या हितग्राही की आकस्मिक मृत्यु/स्थायी अपंगता/असाध्य बीमारी होने की वशा में प्राप्त होगा।

5 रुपए में भोजन थाली

प्रदेश में राज्य शासन द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार प्रदेश की 257 मंडी समितियों में कृषि उपज के विक्रय के लिए आर कृषकों को 5 रुपए में भोजन थाली उपलब्ध कराने की योजना लागू की गई।

कृषि विपणन पुरस्कार

प्रदेश में मंडियों में प्रत्येक वर्ष में 2 बार सर्वश्रेष्ठ उत्तीर्ण एवं बलसाम उत्तीर्ण के अवसर पर लॉटर प्रणति द्वारा 50 लाख तक के पुरस्कार में क प्रवर्ग की मंडी समिति में 35 अथ शक्ति का टेक्टर एवं ख, ग तथा घ प्रवर्ग की मंडी समितियों में 50 हजार तक के कृषि यंत्र दिए जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त मंडी के श्रेणी अनुसार एक हजार से 21 हजार तक की वार्षिक रूप में पुरस्कार दिए जाते हैं।

400 से 500 रुपए प्रति किंटल के भाव से प्याज बेचनी पड़ रही

मध्यप्रदेश-महाराष्ट्र में प्याज की गिरती कीमतों से किसान बेहाल

भोपाल। जागत गांव हमार

देश में इन दिनों नई प्याज की आवक के कारण थोक कीमतों में भारी गिरावट देखी जा रही है। कई थोक मंडियों में प्याज की कीमतें काफी निचले स्तर पर बनी हुई हैं, जिससे किसानों को तगड़े नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। खासकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में प्याज किसानों को बुरा हाल है। महाराष्ट्र की कुछ मंडियों में किसानों को 4-5 रुपए प्रति किंटल यानी 400 से 500 रुपए प्रति किंटल के भाव से प्याज बेचनी पड़ रही है। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब प्याज की आवक और तेजी से बढ़ेगी और दाम भी तेजी से गिरेंगे। हालांकि, दक्षिण में केरल में अभी किसानों को कीमतें बढ़िया मिल रही हैं।

आवक बढ़ने का कारण- आवक बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यह है कि इस बार लेट रबी सीजन वाली प्याज का बंपर उत्पादन हुआ है। यह प्याज जल्दी सड़ती है, इसलिए इसका भंडारण नहीं किया जा सकता। यही चजह है कि किसान बाजार में इसे बेचने की कोशिश में हैं, ताकि कुछ कीमत तो मिल जाए और पूरी फसल का नुकसान न हो।

महाराष्ट्र की मंडियों में प्याज का भाव

मंडी	न्यूनतम कीमत	अधिकतम कीमत	औसत कीमत
करजात	500	2500	1500
चंद्रपुर	2000	2600	2300
मनमाड	400	2580	2200
सांगली	1000	3100	2050
पिंपलगांव	500	2910	2100
येवला	600	2426	2000
पुणे	1500	2500	2000
पुणे	1500	2700	2100
नासिक	950	2485	2175
लासगांव	1000	2570	2250

देश की अन्य मंडियों में प्याज का भाव

मंडी	न्यूनतम कीमत	अधिकतम कीमत	औसत कीमत
चोंगावन्नूर, केरल	6500	7000	6800
थोडुपुडा, केरल	3300	3500	3500
कन्नूर, केरल	3500	3700	3600
आंचल, केरल	3700	3900	3800
कोयिलैंडी, केरल	3400	3500	3500
कुल्लू, हिमाचल	2700	3000	3000
नारायणगढ़, हरियाणा	1800	2400	2000
पंचकूला हरियाणा	2500	2800	2500
रेवाड़ी, हरियाणा	1000	3000	2000
सोनीपत, हरियाणा	2100	2400	2100
मंदसौर, मध्य प्रदेश	699	1154	1154
रतलाम, मध्य प्रदेश	720	1999	1999
उज्जैन, मध्य प्रदेश	400	2100	2100
शाजापुर, मध्य प्रदेश	468	2199	510

जागत गांव हमार, सलाहकार मंडल

- प्रो. डॉ. के.आर. मौर्य**, पूर्व कुलपति, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पुरासामन्तीपुर (बिहार) एवं मालवा ज्योतिरियन फूले विश्वविद्यालय, जयपुर (राजस्थान)
ईमेल- kuber.ram@gmail.com, मोबा- 7985680406
- प्रो. डॉ. वैश्विक लाल, प्रोफेसर**, आनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग, सैम हिंगिन बॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, टेननालोजी एंड सॉलरिज, प्रयागराज, उप्र। ईमेल- vishwakalyal.lal@shiats.edu.in, मोबा- 7052657380
- डा. बीरेन्द्र कुमार**, प्रोफेसर एंड हेड, पौध रोग विज्ञान विभाग, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय परिसर डोली, मुजफ्फरपुर, बिहार। ईमेल- birendraray@gmail.com, मोबा- 8210231304
- डा. नरेश चन्द्र गुप्ता, वैज्ञानिक**, मृदा विज्ञान, कृषि महाविद्यालय बिरसा, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कोके, राँची झारखण्ड। ईमेल- ncguptabau@gmail.com, मोबा- 8789708210
- डा. देवेन्द्र पाटिल, वैज्ञानिक** (शस्य विज्ञान) कृषि विज्ञान केन्द्र, सीहोर (मध्यप्रदेश) सेवनिया, इछवर, सीहोर (मप्र) ईमेल- dpatil889@gmail.com, मोबा- 8827176184
- डा. आशुतोष कुमार सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर**, एग्री विजनेस मैनेजमेंटकृषि अर्थशास्त्र विभाग, एकेएच, विश्वविद्यालय, सतना, मप्र ईमेल- kumar.ashu777@gmail.com, मोबा- 8840014901
- डा. विनीता सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर** आनुवांशिकी एवं पौध प्रजनन विभाग एकेएस विश्वविद्यालय, सतना, मप्र ईमेल- singhvineeta123@gmail.com, मोबा- 8840028144
- डा. आरके शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर**, परिसर विज्ञान विभाग, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना, बिहार। ईमेल- drkrsharmabvc@gmail.com, मोबा- 9430202793
- डा. दीपक कुमार, सहायक प्राध्यापक**, मृदा एवं जल संरक्षण अभियांत्रिकी विभाग, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर, उत्तराखण्ड। ईमेल- deepak.swcc.cot.gbpuat@gmail.com, मोबा- 7817889836
- डा. भारती उपाध्याय, विषय वस्तु विशेषज्ञ** (शस्य विज्ञान) कृषि विज्ञान केन्द्र, किरौली, समस्तीपुर, बिहार। ईमेल- bharati.upadhyay@rpcau.ac.in, मोबा- 8473947670
- रोमा वर्मा**, सक्नी विज्ञान विभाग महात्मा गांधी स्नातकी एवं वाणिज्य विश्वविद्यालय, पाटन, जिला- दुर्ग, छत्तीसगढ़। ईमेल- romaverma35371@gmail.com, मोबा- 6267535371

समर्थन पर गेहूं बेचने 62 हजार किसानों ने कराया पंजीयन

भोपाल। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि अभी तक 62 हजार 77 किसानों ने पंजीयन कराया है। किसान 31 मार्च तक पंजीयन करा सकते हैं। उन्होंने बताया है कि वर्ष 2025-26 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपए घोषित किया गया है। यह तब तक 150 रुपए अधिक है। मंत्री ने किसानों से आह्वान किया है कि गेहूं की बिक्री के लिए समय-समय में पंजीयन जरूर कराएं। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की बिक्री के लिए जिला बुरहानपुर में 2, बड़वानी में 17, खरगोन में 189, खंडवा में 339, अलीराजपुर में 13, झाबुआ में 776, धार में 4202, इंदौर में 9381, नीमच 134, मंदसौर 362,

आगर-मालवा में 823, शाजापुर में 3710, देवास में 4035, रतलाम में 2211, उज्जैन में 11344, ग्वालियर में 55, शिवपुरी में 23, गुना में 23, दतिया में 142, अशोकनगर में 6, भिंड में 4, मुरैना में 96, श्योपुर में 43, छिंदवाड़ा में 157, सिवनी में 61, कटनी में 14, नरसिंहपुर में 215, मंडला में 353, हरदा में 173, बैतूल में 362, नर्मदापुरम में 1793, विदिशा में 1563, भोपाल में 1975, सीहोर में 12596, सतना में 48, सीधी में 75, रीवा में 44, सिंगरौली में 19, मैर में 3, उमरिया में 64, अनुपपुर में 9, शहडोल में 239, सागर में 419, दमोह में 124, छतरपुर में 289, निवाड़ी में 88 और टिकमगढ़ में 341 किसानों ने पंजीयन कराया है।

जागत गांव हमार के सुधि पाठकों...

» जागत गांव हमार कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास आधारित समाचार पत्र है, जिसके लिए आपका स्नेह और प्यार हमें शुरू से मिलता रहा है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा।

» समाचार पत्र के लिए विशेषज्ञों की राय, प्रकाशन योग्य सामग्री के साथ-साथ आपके समक्ष इसे पहुंचाने तक हमारी जिम्मेदारी बड़ी चुनौतीपूर्ण है। आपके सहयोग से ही हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे।

» ऐसे में हमारी आपसे अपेक्षा और आवाह है कि जागत गांव हमार के वार्षिक सदस्य बनें और इसके लिए नीचे लिखे गए नंबर पर संपर्क करें।

संपर्क करें- अजय द्विवेदी-9229497393, 9425048589

“आपका सहयोग हमारी मजबूती का आधार बनेगा”